रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939
No. 1960] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

का.आ. 2201(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 251(अ), तारीख 27 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य, रायपुर प्रभाग, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य 244.66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य अपने समृद्ध पर्यावास के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी और वनस्पति हैं। मुख्य प्रजातियों में तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), जंगली भैंसा (*बिसन बिसन*), रीछ (*मेलुरसस उर्सिनस*), सांभर (*रुसा यूनीकोलोर*), ब्लू बुल (*बोसेलफस ट्रागोकैमेलस*), चित्तीदार हिरण (*रुसा अल्फ्रेडि*), मुंजक (*मुनटियाकस एसपी*) , लकड़बग्घा (*हेयना एसपी*), भेडिया (*कैनिस ल्यूपस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), लोमड़ी (*वल्प्स वल्प्स*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), नेवला (*हेर्पेस्टिडे एपी*), खरगोश (*लिपस एसपी*), सामान्य लंगूर (*सेम्नोपेटेकस इन्टेलस*), जंगली कुत्ता (*लाइकाओन पिक्टस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस*), आदि हैं । महत्वपूर्ण पुष्प प्रजातियां शतावरी (*असपरागस रेसस्मॉस*), धवरा (*अनोगेसस लैटिफ़ोलिया*), कुसुम (*श्लेचेरा*

ओलिसा), आदि और यह महानदी और उसकी सहायक नदियों – बालमदेही और जोंक नदियों पर जल आवाह क्षेत्र का भी निर्माण करता है;

और, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक, पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 7.2 किलोमीटर तक 182.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 7.2 किलोमीटर तक 182.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा में विभाजित बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध I-क** में है।

(3) मुख्य बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंध का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव सम्मिलित होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(5) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ;
(ix) सिंचाई ; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना ;
(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
(iii) वर्षा जल संचयन; और
(iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्राम उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं भी हैं:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध और निर्बंधित करने के लिए ऐसी रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना के मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। जो कोई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनके परिरक्षण और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव-निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए विनियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री पारिस्थितिक संवेदी जोन बाह्य पहचान की गई स्थल पर स्वीकार्य रीति में व्ययित किया जाएगा ;

(iii) ठोस अपशिष्टों के ज्वलन या भस्मीकरण और भराई का स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञा नहीं की जाएगी ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में मौजूद व्यक्तिगत अस्पतालों या निजी स्वास्थ्य केंद्रों के संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल असर से बचने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, प्रदूषण नियंत्रण कारित कोई नए उद्योग स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।।

(16) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका

		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	(जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण) इत्यादि कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा गैर प्रदूषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।
5.	नई मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रालाइट, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा की अतिरिक्त स्थापना प्रतिषिद्ध है ।
11.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

IndiaCode

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
13.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के पश्चात् या विस्तार तक पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलामीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (iv) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची।
15.	खाई का मैदान।	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है | पुराने खाई के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं |
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
18.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	सतह और भूजल की वाणिज्यिक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	निकासी ।	
21.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
22.	प्रवासी चारागाहे ।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	विद्यमान प्रतिष्ठापन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
25.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
26.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण। (एन.टी.एफ.पी.)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
29.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
30.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
34.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
35.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

40.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
41.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
46.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	कलक्टर, जिला, बलौदा बाजार	अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदा बाजार	सदस्य;
(iii)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, बलौदा बाजार	सदस्य;
(iv)	अधीक्षण इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग, बलौदा बाजार	सदस्य;
(v)	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव, पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	सदस्य/सदस्यसचिव-, राज्य जैव विविधता बोर्ड-	सदस्य;
(viii)	छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	अधीक्षक, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य; और
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी, बलौदा बाजार	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन .-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

IndiaCode

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(3) निगरानी समिति पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को भी अनुज्ञात नहीं करेगा केवल श्वेत उद्योग प्रवर्ग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उद्योगों का वर्गीकरण), 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शकों ने यथा विनिर्दिष्ट माना जाएगा ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उनके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

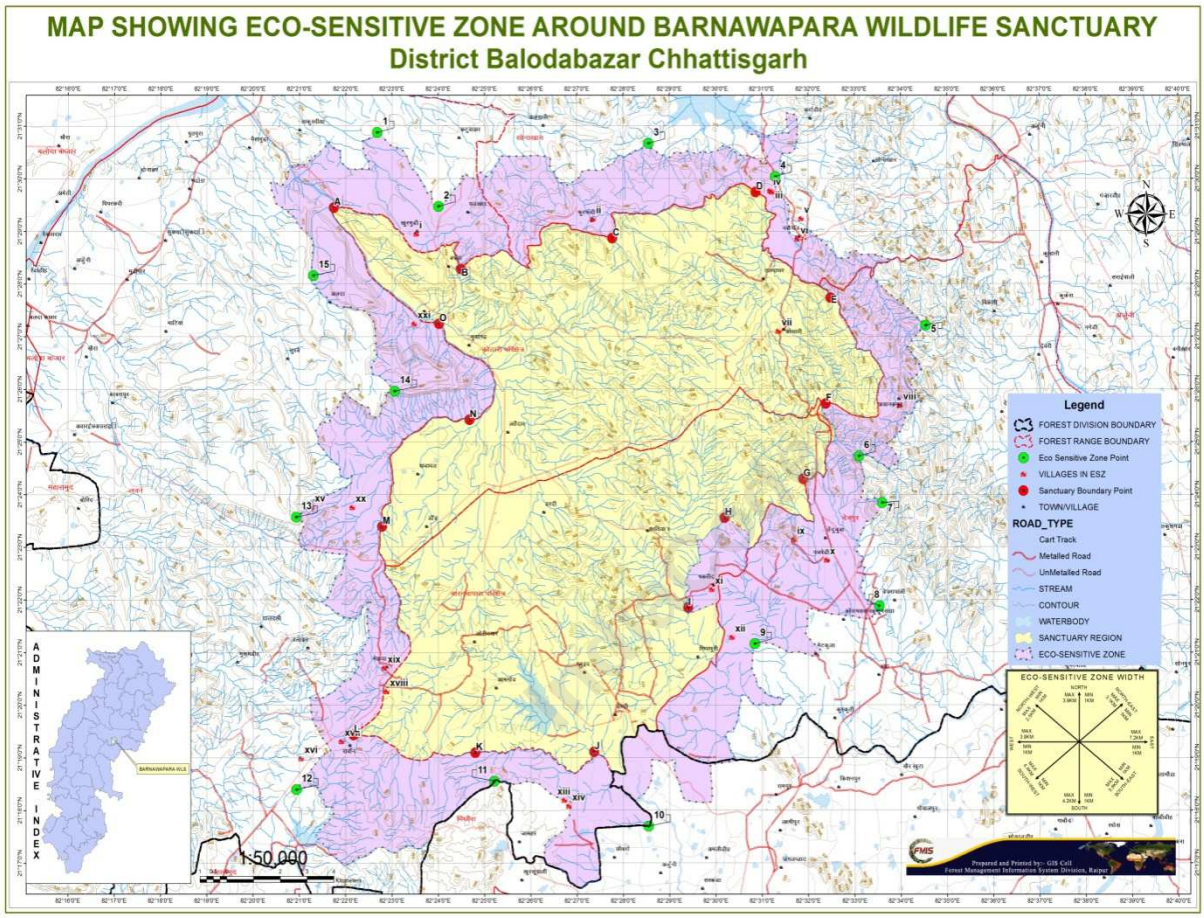
8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/151/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध–I

पारिस्थितिक संवेदी जोन सहित बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध–I(क)

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	ए	21°29'27.2904''	82°21'44.8776''
2	बी	21°28'17.31''	82°24'29.6172''
3	सी	21°28 '52.4388''	82°27'46.0548''
4	डी	21°29'44.9016''	82°30'52.0776''
5	ई	21°27'44.4888''	82°32'29.0544''
6	एफ	21°25'43.95''	82°32'22.6572''
7	जी	21°24'18.0756''	82°31'53.4252''
8	एच	21°23'33.8496''	82°30'11.5056''
9	आई	21°21'51.3468''	82°29'24.1872''
10	जे	21°19'7.2012''	82°27'22.2624''
11	के	21°19'6.3696''	82°24'48.3012''
12	एल	21°19'26.508''	82°22'10.5312''

IndiaCode

13	एम	21°23'23.7876''	82°22'47.5392''
14	एन	21°25'25.716''	82°24'40.6512''
15	ओ	21°27'15.0732''	82°24'1.3068''

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	1	21°30'52.9452''	82°22'41.0484''
2	2	21°29'28.6368''	82°24'0.4716''
3	3	21°30'40.3488''	82°28'32.9412''
4	4	21°30'2.61''	82°31'17.4216''
5	5	21°27'13.0572''	82°34'32.4732''
6	6	21°24'44.1072''	82°33'5.6124''
7	7	21°23'50.9892''	82°33'36.0072''
8	8	21°21'53.4096''	82°33'32.22''
9	9	21°21'10.296''	82°30'50.7888''

IndiaCode

10	10	21°17'42.522''	82°28'32,7792''
11	11	21°18'33.6168''	82°25'12.9648''
12	12	21°18'24.1308''	82°20'56.2632''
13	13	21°23'34.5516''	82°20'55.9284''
14	14	21°25'58.1628''	82°23'3.5556''
15	15	21°28'9.7896''	82°21'18.072''

उपाबंध II

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
i	खुरमुरी	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 28' 57"	82° 23' 32"
ii	फुरफुंदी	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 29' 14"	82° 27' 21"
iii	घटमुरवा1	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 29' 45"	82° 31' 13"
iv	कोन्जिया	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 29' 46"	82° 31' 11"
v	जोगीदिपा	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 29' 15"	82° 31' 51"
vi	नवागांव 1	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 28' 51"	82° 31' 46"
vii	तलाददार	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 27' 6"	82° 31' 21"

viii	अचानकपुर	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 25' 42"	82° 33' 59"
ix	तेंदुछुआ	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 23' 9"	82° 31' 41"
x	धवालपुरा	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 22' 45"	82° 32' 24"
xi	पकरिद	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 22' 12"	82° 29' 55"
xii	गिधपुरी	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 21' 18"	82° 30' 21"
xiii	जमहार 8	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 18' 12"	82° 26' 43"
xiv	जमहार 7	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 18' 5"	82° 26' 50"
xv	जमहार 2	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 23' 46"	82° 21' 16"
xvi	लदादिह	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 18' 59"	82° 21' 3"
xvii	रावन	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 19' 19"	82° 21' 55"
xviii	धेबिखार 1	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 20' 16"	82° 22' 53"
xix	मोहदा	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 20' 42"	82° 22' 50"
xx	सहियाभाटा	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 23' 46"	82° 22' 9"
xxi	भिनमोरी	राजस्व	कसदोल	बलौदा बाजार	21° 27' 15"	82° 23' 29"

IndiaCode

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 12th July, 2017

S.O. 2201(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 251 (E) dated the 27th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments/objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Barnawapara Wildlife Sanctuary is located in Raipur Division, Balodabazaar, District in the State Chhattisgarh and is located at a distance of about 100 kilometres from Raipur and the Barnawapara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 244.66 square kilometres;

AND WHEREAS, the Barnawapara Wildlife Sanctuary forms an important protected area for its rich habitat of a variety of flora and fauna. Key species include Leopard (*Panthera pardus*), Bison (*Bison bison*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Sambhar (*Rusa unicolor*), Blue Bull (*Boselaphus tragocamelus*), Spotted Deer (*Rusa alfredi*), Barking Deer (*Muntiakus sp*.), Hyena (*Hyaena sp*.), Wolf (*Canis lupus*), Jackal (*Canis aureus*), Fox (*Vulpes vulpes*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Mongoose (*Herpestidae sp*.), Hares (*Lepus sp*.), Common Langur (*Semnopithecus entellus*), Wild Dog (*Lycaon pictus*), Wild Boar (*Sus scrofa domesticus*), etc. Important floral species include Satavar (*Asparagus recemosus*), Dhawra (*Anogeissus latifolia*), Kusum (*Schleichera oleosa*), etc and it forms a watershed for the River Mahanadi and its tributaries – the Balamdehi and Jonk rivers;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Barnawapara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 1 kilometre to 7.2 kilometres of 182.5 square kilometres around the boundary of Barnawapara Wildlife Sanctuary in the State of Chhattisgarh as the Barnawapara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 182.5 square kilometres with an extent ranging from 1 kilometre to 7.2 kilometres around the boundary of Barnawapara Wildlife Sanctuary.

(2) The map of Barnawapara Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is appended at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates is at **Annexure I (A)**.

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Chhattisgarh Environment Conservation Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

IndiaCode

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) widening and strengthening of existing roads;

(ii) small scale industries not causing pollution;

(iii) rainwater harvesting; and

(iv) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Eco-tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Chhattisgarh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Chhattisgarh.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Barnawapara Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment

IndiaCode

of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000, under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(iii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco-sensitive Zone should provide adequate waste treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) **E- waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely-

IndiaCode

Sl. No.	Activity	Remarks
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

	hazardous substances.	laws.
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
5.	Establishment of new major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive Zone. Further, installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
12.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of

IndiaCode

		the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as,- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.
15.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
16.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
17.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
18.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
21.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Act and

IndiaCode

		the rules made thereunder.
22.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
23.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
24.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
25.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
26.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
29.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
30.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
32.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
34.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
40.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture,

IndiaCode

		horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
41.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
42.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i.) Collector, District, Balodabazar - Chairman;

(ii.) Chief Executive Officer, District Panchayat, Balodabazar - Member;

(iii.) Superintending Engineer, Public Work Department Balodabazar - Member;

(iv.) Superintending Engineer Public Health Department Balodabazar - Member;

(v.) One expert in the area of wildlife, ecology and environment to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of three years in each case - Member;

(vi.) Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of three years in each case. - Member;

(vii.) Member/ Member Secretary, State Biodiversity Board - Member;

(viii.) Representative of Chhattisgarh Pollution Control Board - Member;

(ix.) Superintendent, Barnawapara Wildlife Sanctuary - Member; and

(x.) Divisional Forest Officer, Balodabazar -Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. number 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide number S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of

IndiaCode

industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to Ministry of Environment Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

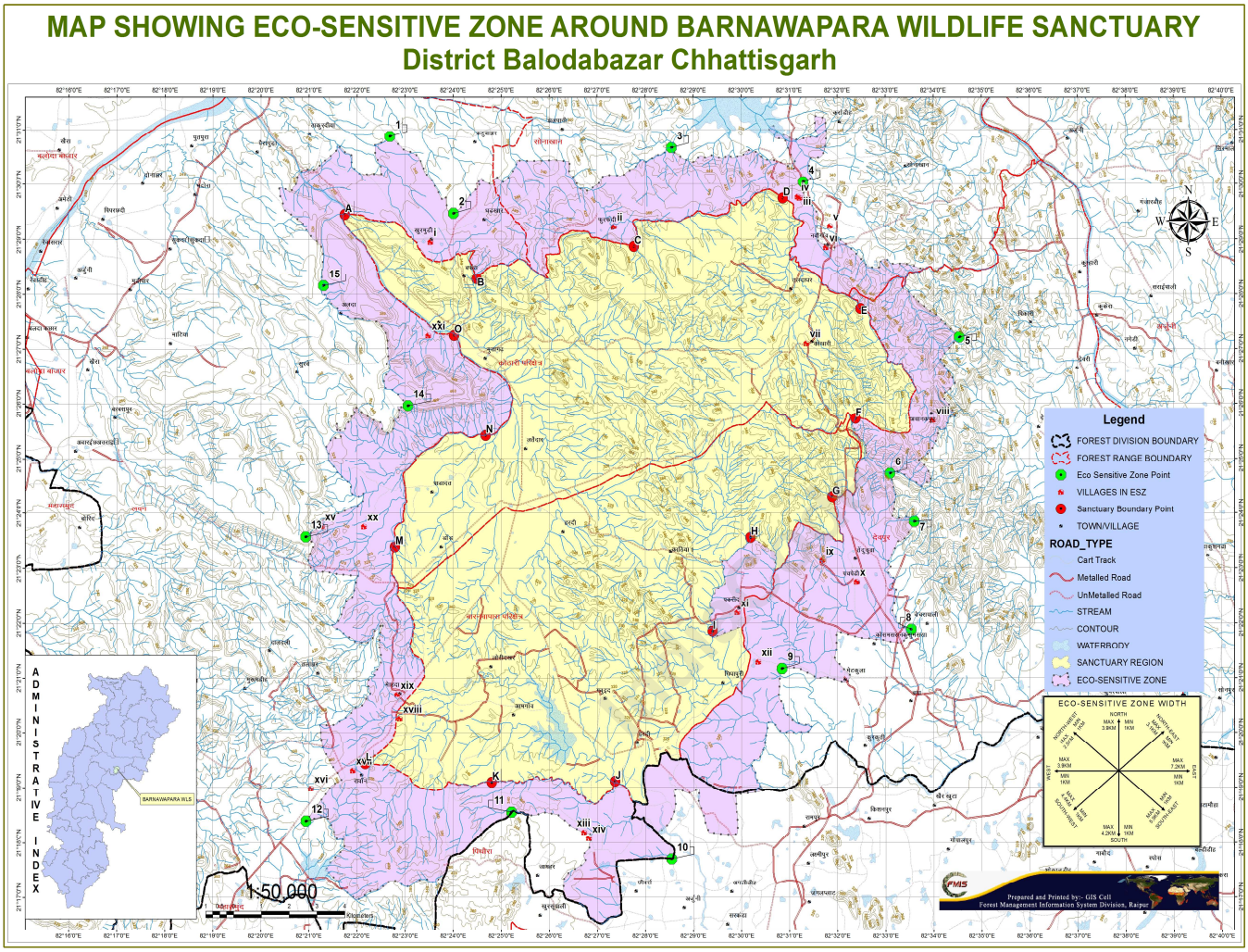
[F. No. 25/151/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

Map of Barnawapara Wildlife Sanctuary along with its Eco- Sensitive Zone



Annexure I (A)

Geo Co-ordinates of Boundary of Barnawapara Wildlife Sanctuary

Sl. No	Identification of Prominent Points	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	A	21°29'27.2904''	82°21'44.8776''
2	B	21°28'17.31''	82°24'29.6172''
3	C	21°28 '52.4388''	82°27'46.0548''
4	D	21°29'44.9016''	82°30'52.0776''

5	E	21°27'44.4888''	82°32'29.0544''
6	F	21°25'43.95''	82°32'22.6572''
7	G	21°24'18.0756''	82°31'53.4252''
8	H	21°23'33.8496''	82°30'11.5056''
9	I	21°21'51.3468''	82°29'24.1872''
10	J	21°19'7.2012''	82°27'22.2624''
11	K	21°19'6.3696''	82°24'48.3012''
12	L	21°19'26.508''	82°22'10.5312''
13	M	21°23'23.7876''	82°22'47.5392''
14	N	21°25'25.716''	82°24'40.6512''
15	O	21°27'15.0732''	82°24'1.3068''

IndiaCode

Geo Co-ordinates of Boundary of Eco-Sensitive Zone of Barnawapara Wildlife Sanctuary

Sl. No	Identification of Prominent Points	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	21°30'52.9452''	82°22'41.0484''
2	2	21°29'28.6368''	82°24'0.4716''
3	3	21°30'40.3488''	82°28'32.9412''
4	4	21°30'2.61''	82°31'17.4216''
5	5	21°27'13.0572''	82°34'32.4732''
6	6	21°24'44.1072''	82°33'5.6124''
7	7	21°23'50.9892''	82°33'36.0072''
8	8	21°21'53.4096''	82°33'32.22''
9	9	21°21'10.296''	82°30'50.7888''

10	10	21°17'42.522''	82°28'32,7792''
11	11	21°18'33.6168''	82°25'12.9648''
12	12	21°18'24.1308''	82°20'56.2632''
13	13	21°23'34.5516''	82°20'55.9284''
14	14	21°25'58.1628''	82°23'3.5556''
15	15	21°28'9.7896''	82°21'18.072''

Annexure II

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Barnawapara Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh

Sl. No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
i	Khurmuri	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 28' 57"	82° 23' 32"
ii	Phurphundi	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 29' 14"	82° 27' 21"
iii	Ghatmurwa1	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 29' 45"	82° 31' 13"
iv	Konjia	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 29' 46"	82° 31' 11"
v	Jogidipa	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 29' 15"	82° 31' 51"
vi	Nawagoan 1	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 28' 51"	82° 31' 46"
vii	Taladadar	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 27' 6"	82° 31' 21"
viii	Achanakpur	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 25' 42"	82° 33' 59"
xi	Tenduchhua	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 23' 9"	82° 31' 41"
x	Dhawalpura	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 22' 45"	82° 32' 24"
xi	Pakrid	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 22' 12"	82° 29' 55"
xii	Gidhpuri	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 21' 18"	82° 30' 21"
xiii	Jamhar 8	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 18' 12"	82° 26' 43"
xiv	Jamhar 7	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 18' 5"	82° 26' 50"
xv	Jamhar 2	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 23' 46"	82° 21' 16"
xvi	Ladadih	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 18' 59"	82° 21' 3"
xvii	Rawan	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 19' 19"	82° 21' 55"
xviii	Dhebikhar 1	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 20' 16"	82° 22' 53"
xix	Mohda	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 20' 42"	82° 22' 50"
xx	Sahiyabhata	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 23' 46"	82° 22' 9"
xxi	Bhinmori	Revenue	Kasdol	Balodabazar	21° 27' 15"	82° 23' 29"

Annexure III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.15 16:18:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.